विधान सभाओं के प्रति अथवा राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में संसद के प्रति जवाबदेह होती है । किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को संकटपूर्ण नही कहा जा सकता और हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी राज्य दिवालियेपन को छूने की स्थिति में नही है । दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओर से वित्त मंत्रालय को 139573.01 करोड़ रुपए की देयराशि बकाय थी । तथापि, यह राशि तत्काल पुर्नअदायगी के लिए बकाया नही है । वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यों द्वारा मूल और ब्याज के रूप में वित्त मंत्रालय को 19737.83 करोड़ रुपये पुनर्भुगतान करना है । राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण – पत्र में दर्शाया गया है । (नीचे देखिए)

(ग) राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान एक सामान्य प्रक्रिया है । ज्यादातर मामलों में राज्य सरकारें स्वयं पुनर्भुगतान कर देती है । कुछेक मामलों में ऋण के पुनर्भुगतान को राज्य सरकारों के केन्द्रीय अंतरण/आवंटन के स्थान पर समायोजित किया जाता है ।

विवरण

दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार राज्यवार बकाया राशि तथा 1996-97 के दौरान मूल तथा ब्याज के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को पुनअदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपए में)

राज्य	31.12.97 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	1996-97 के दौरान पुनअदा की गई धनराशि
1. आंध्र प्रदेश	10501.70	1412.61
2. अरूणाचल प्रदेश	185.94	30.88
3. असम	3649.91	548.52
4. बिहार	9385.04	1316.82
5. गोवा	800.54	85.67
6. गुजरात	9433.40	1373.79
7. हरियाणा	3489.34	597.08
8.हिमाचल प्रदेश	1635.14	212.62
9. जम्मू कश्मीर	2788.51	412.14
10. कर्नाटक	6560.22	926.53
11. केरल	4498.51	646.44
12. मध्य प्रदेश	6232.44	893.94
13. महाराष्ट्र	15565.23	2132.83
14. मणिपुर	195.47	27.03
15. मेघालय	228.97	34.44
16. मिजोरम	142.05	19.72
17. नागालैण्ड	241.29	35.67
18. उडीसा	4560.64	640.84
19. पंजाब	10460.42	1587.28
20. राजस्थान	6765.46	927.69
21. सिक्किम	131.03	18.58
22. तमिलनाडु	8283.94	1165.74
23. त्रिपुरा	339.97	51.88
24. उत्तर प्रदेश	20781.56	2920.32
25. पश्चिम बंगाल	12708.29	1727.97
कुल	139573.01	19737.03

Letters Received by SBI Central Office Mumbai Regarding State Bank of Indore

1062. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of letters received from the Members of Parliament by State Bank of India, Central Office, Mumbai during November-December, 1995 complaining that higher authorities of State Bank of Indore at Delhi are shielding some guilty employees;

(b) if so, whether an impartial enquiry of these letters has been conducted by the Central Office, Mumbai; and

(c) what directions are likely to be given regarding action against guilty employees and the officers; if not, the reasons for inordinate delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

मूल खाध पदार्थो के डब्ल्यू0पी0आई0 में अन्तर होने के संबंध में प्रकाशित समाचार

1063. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे किः-

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1996 के "दि इकनोमिक्स टाइम्स" में' हायर वैरीएशन इन डब्ल्यू पी0आई0 ऑफ बेसिक फूडस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में आम आदमी के प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे गेहूं, चना, नारियल का तेल, आलू और आटा की कीमतों में दिसम्बर, 1993-94, दिसम्बर, 1994-95 और दिसम्बर, 1995-96 में निरन्तर वृध्दि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 पी0 वीरेन्द्र कुमार) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक की चार वर्षो की अवधि के लिए दिसम्बर के अंत तक विनिर्दिष्ट खाध मदों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) द्वारा मापित मूल्य वृध्दि की मात्रा नीचे सूचीबध्द है :-

थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृध्दि

(दिसम्बर अंत के अनुसार)

मदें	प्रतिशत वृध्दि			
	1993	1994	1995	1996
गेहूं	13.1	9.7	-1.6	31.3
चना	74.7	-10.3	-38.3	47.3
नारियल का तेल	26.7	12.1	0.3	46.8
आलू	58.2	-15.3	7.4	80.9
आटा	5.8	6.4	3.5	43.3

उक्त पांच वस्तुओं, जिन्होंने दिसम्बर, 1996 में उच्च वार्षिक मूल्य वृध्दि दर्ज की है, की तुलना में अन्य प्राथमिक वस्तुओं ने या तो गिरावट दर्ज की है या उनमें काफी कम वृध्दि हुई है जैसे चावल (13 प्रतिशत), अरहर(-1.3 प्रतिशत), प्याज(-215.5 प्रतिशत), चाय (-4.3 प्रतिशत), सरसों का तेल(-7.9 प्रतिशत), मूंगफली का तेल (-3.4 प्रतिशत), वनस्पति (-2.6 प्रतिशत), बाजरा(3.9 प्रतिशत), उड़द(11.5 प्रतिशत), दूध(2.9 प्रतिशत) और चीनी (1.2 प्रतिशत)।

करेंसी नोटो की कमी के संबंध में प्रकाशित समाचार

1064. **श्री राम जेठमलानी** ; क्या वित्त मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "प्रिमियम ओन फ्रेश मंडलस गेनिंग करेंसी इन सिटी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि देश में छोटी कागजी करेंसी की उपलब्धता में भारी कमी होने के कारण छोटी करेंसी के नए नोट काले बाजार में उपलब्ध है;

(ग) यदि नही, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जून, 1996 से लेकर अब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक महीने में, 1,2 और 5 रुपए के नए करेंसी नोटा औसतन कुल कितने मूल्य के जारी किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0पी0 वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को निम्न मूल्यवर्ग के नए नोटो के लिए अदा किए जा रहे किसी प्रीमियम के बारे में जानकारी नही है।

(ग) और (घ) सरकारी नीति के अनुसार, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण कर दिया गया है। तदनुसार, नोट प्रिटिंग प्रेसों ने क्रमशः सितम्बर, 1994, जनवरी 1995 और नवम्बर, 1995 से इन मूल्यवर्गो के नोटो की छपाई बंद कर दी है।

Directive Regarding Reservation to SC/ ST Employees in Punjab and Sind Bank

1065. DR. RANBIR SINGH:

SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether some directives have been issued to the management of Punjab and Sind Bank to provide reservation for SC/ST employees against promotion given to 48 officers from JMGS-I to MMGS-II in 1994 under normal channel of promotion policy;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the provisions of said directives have since been implemented; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) It is reported by the Punjab & Sind Bank, that High Court of Punjab & Haryana, in a Judgement dated 22.12.95 issued direction to the Bank to provide reservations for SC/ST employees as